गुरुवार , 05 नवंबर 2026, ठाणे, मुंबई

दैनिक सिटी न्यूज मुंबई

सच का जोश

वर्ष - 15 • अंक - 70 CITY NEWS MUMBAI

गोकुल डेयरी विवाद: राहुल गांधी ने सरकार पर लगाया जनादेश चोरी का आरोप

महाविकास आघाड़ी क्यों हुई हमलावर?

कोल्हापुर की गोकुल डेयरी के चुनावों में कांग्रेस समर्थित पैनल द्वारा बहुमत हासिल करने के बावजूद, महाराष्ट्र सरकार द्वारा सहकारिता नियमों में बदलाव कर चार अतिरिक्त सरकारी निदेशक नियुक्त करने के फैसले पर राज्य में भारी राजनीतिक बवाल मच गया है। राहुल गांधी और महाविकास आघाड़ी के अन्य नेताओं ने इसे जनता के जनादेश की चोरी बताते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है, जबकि विपक्ष ने इसके खिलाफ 9 नवंबर को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और डेयरी घेराव का ऐलान किया है। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त कोल्हापुर की मशहूर 'गोकुल डेयरी' (कोल्हापुर जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ) को लेकर घमासान मचा हुआ है। राज्य की सत्ता पर काबिज महायुति सरकार और विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी (एमवीए) के बीच सहकारिता के इस अहम केंद्र



पर कब्जा जमाने को लेकर सीधी जंग शुरू हो चुकी है। हाल ही में हुए चुनावों में कांग्रेस समर्थित पैनल ने जीत दर्ज की थी, जिसके बाद से राजनीतिक बयानबाजी और विरोध प्रदर्शनों का दौर तेज हो गया है। विपक्षी दलों का साफ आरोप है कि सरकार चुनाव हारने के बाद अब पिछले दरवाजे से नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रही है। सहकारिता चुनाव में किसे मिली थी जीत? 19 अक्तूबर को हुए गोकुल डेयरी के चुनावों में कांग्रेस नेता सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले पैनल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 25 में से 13 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि सत्ताधारी गठबंधन समर्थित पैनल को 12 सीटें मिली थीं। चुनाव नतीजों के बाद चेयरमैन पद का चुनाव होना था, लेकिन सत्ताधारी खेमे के 12 निर्देशकों के गैर-हाजिर रहने के कारण चुनाव टल गया, जिसके बाद मामला बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। अदालत ने सभी 25 निर्देशकों को नोटिस जारी करते हुए 10 नवंबर को चेयरमैन का चुनाव कराने का निर्देश दिया, और सरकार ने भी अदालत के सामने स्पष्ट किया था कि चुनाव इन्हीं 25 लोगों के बीच कराया जाएगा। सरकार के किस फैसले पर भड़के नेता? अदालत के निर्देश के बावजूद राज्य कैबिनेट ने बुधवार को एक नया अध्यादेश पास कर दिया, जिसके तहत 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले सहकारी संस्थानों में चार अतिरिक्त सरकारी नामांकित निर्देशकों को वोटिंग अधिकार के साथ नियुक्त करने का रास्ता साफ हो गया। इस फैसले को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे 'जनादेश के साथ मिलावट' और दूध उत्पादकों के वोटों की खुली चोरी करार दिया। वहीं, शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव हारने के बाद अपनी संख्या बल को जबरन बढ़ाने के लिए ही यह अध्यादेश लाया गया है। महाविकास आघाड़ी का अगला कदम क्या होगा? कोल्हापुर के स्थानीय स्तर से लेकर मुंबई तक इस फैसले के खिलाफ भारी नाराजगी ...शेष 7 पर

हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को बड़ी राहत, निर्वाह भत्ते में भारी बढ़ोतरी; मंत्रिमंडल के 12 फैसले

सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 12 बड़े फैसले। छात्रावास भत्ता दोगुना, ट्रैफिक चालान के लिए अभय योजना-2026 और 73 लाख किसानों को 5,000 की मदद। महाराष्ट्र कैबिनेट के 12 फैसले, छात्रों का भत्ता बढ़ा। लंबित ट्रैफिक चालान पर अभय योजना-2026 को मंजूरी। 73 लाख किसानों को 5,000 मिले, नागपुर में 644 करोड़ का कृषि केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विद्यार्थियों, वाहन चालकों और



सहकारी संस्थाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए 12 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। अन्य पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति, घुमंतू जनजाति और विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के निर्वाह भत्ते में दोगुने से अधिक वृद्धि की गई है। वहीं, यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर लगे लंबित जुर्माने के भुगतान के लिए वाहन चालकों को एकमुश्त राहत देने वाली अभय योजना-2026 को मंजूरी दी गई है। पशु चिकित्सा के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के इंटर्नशिप भत्ते में भी वृद्धि का निर्णय लिया गया। अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग के छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के निर्वाह भत्ते में वृद्धि की गई है। विभागीय स्तर के छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को अब प्रतिमाह 1,500 रुपये, जबकि जिला स्तर के छात्रावासों के विद्यार्थियों को 1,300 रुपये मिलेंगे। इससे ...शेष 7 पर

शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने का मुद्दा



शिवसेना पार्टी नाम व चुनाव चिन्ह मामले में सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की दलील- विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से विधायकों की अयोग्यता याचिका अब अप्रासंगिक। शिंदे गुट की सुप्रीम कोर्ट में दलील, विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से अयोग्यता याचिका बेअसर। वकील ध्रुव मेहता ने विधानसभा अध्यक्ष के अधिकारों का हवाला दिया। शिंदे गुट ने 2022 में बनी सरकार को पूरी तरह ...शेष 7 पर

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का असर, BMC ने बोरीवली में 27 अवैध निर्माण तोड़े; 3,400 वर्ग मीटर जमीन खाली



सुप्रीम कोर्ट की सख्त कार्रवाई के बाद बीएमसी ने बोरीवली (पूर्व) में BEST बस डिपो की 3,400 वर्ग मीटर जमीन से 27 व्यावसायिक अतिक्रमण ध्वस्त कर भूखंड मुक्त कराया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बीएमसी ने बोरीवली में 27 अवैध निर्माण हटाए। बेस्ट बस डिपो के लिए आरक्षित 3,400 वर्ग मीटर जमीन अतिक्रमण मुक्त हुई। बीएमसी पर 5 लाख जुर्माना, अधिकारियों को निलंबित करने की मांग उठी। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आखिरकार बीएमसी प्रशासन हरकत ...शेष 7 पर

मिरा-भाईंदर को बड़ी सौगात!

ट्रैफिक शाखा के लिए बनेगा स्वतंत्र पुलिस उपायुक्त पद, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मंजूरी

मिरा-भाईंदर,(सिटी न्यूज़ मुंबई) मिरा-भाईंदर शहर में बढ़ती आबादी, वाहनों की संख्या और दिन-ब-दिन गंभीर होती जा रही यातायात जाम की समस्या को देखते हुए ट्रैफिक शाखा के लिए स्वतंत्र पुलिस उपायुक्त (DCP) पद बनाने की मांग को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। इस संबंध में विधायक नरेंद्र मेहता ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष मिरा-भाईंदर-वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत यातायात शाखा के लिए स्वतंत्र पुलिस उपायुक्त पद बनाने की आवश्यकता रखी



थी। शहर की जरूरत को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सकारात्मक निर्णय लेते हुए पुलिस महानिदेशक (DGP) को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में 3 नवंबर 2026 को महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्र पुलिस उपायुक्त पद के निर्माण को आधिकारिक मंजूरी दे दी। इस निर्णय से शहर की यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने और आए दिन लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है।

इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए विधायक नरेंद्र मेहता ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मिरा-भाईंदर के विकास और नागरिकों की सुविधाओं के लिए वे हमेशा प्रतिबद्ध हैं।

राहुल गांधी पर बरसे CM फडणवीस, बोले- 4500 वोट के गोकुल संघ के लिए दिल्ली से ट्वीट करना पड़ रहा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गोकुल दूध संघ चुनाव विवाद पर राहुल गांधी पर हमला बोला। फडणवीस ने कहा कि केवल 4500 मतदाताओं के लिए दिल्ली से हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने गोकुल दूध संघ चुनाव के मुद्दे पर राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर तंज कसा। CM फडणवीस ने कहा दो बार कोरम पूरा न होने के कारण सरकार को कदम उठाना पड़ा। फडणवीस ने कहा कि यह फैसला एडवोकेट जनरल की कानूनी राय लेने के बाद ही लिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोल्हापुर के प्रसिद्ध गोकुल दूध संघ को लेकर छिड़े राजनीतिक विवाद पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। फडणवीस ने राहुल गांधी की राजनीतिक स्थिति पर चुटकी लेते हुए कहा कि यह बेहद हास्यास्पद है कि एक स्थानीय संस्था के चुनाव के लिए राहुल गांधी को दिल्ली में बैठकर ट्वीट करना पड़ रहा है। CM फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला संवाददाताओं से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गोकुल दूध संघ हालिया घटनाक्रम पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की कैसी हालत हो गई है!



गोकुल में केवल 4,500 मतदाता हैं, और इतने छोटे से स्थानीय चुनाव के लिए राहुल गांधी को दिल्ली में बैठकर ट्वीट करना पड़ रहा है। गोकुल के चुनाव में किसी भी एक पक्ष को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। चुनाव परिणामों में एक पक्ष ने 13 सीटें जीती थीं, जबकि दूसरे पक्ष ने 12 सीटें जीती थीं। कोरम न पूरा होने के कारण लिया गया फैसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रशासनिक बताया कि गोकुल दूध संघ की बैठक के लिए आवश्यक कोरम पूरा नहीं हो पा रहा था। सदस्यों की गैरहाजिरी और कोरम की कमी के कारण बैठक को पहले ही दो बार रद्द करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि अगर कोरम की कमी की वजह से यह बैठक तीसरी बार भी रद्द हो जाती, तो नियमानुसार पूरा चुनाव ही रद्द करने की नौबत आ जाती। संस्था के कामकाज और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। कानूनी सलाह के बाद ही हुआ निर्णय विपक्ष द्वारा सरकार के इस फैसले को गैर-कानूनी और असंवैधानिक बताए जाने पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दोटूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यह फैसला अदालत में नहीं टिकेगा, जबकि कानूनी जानकारों का मानना है कि यह निर्णय पूरी तरह वैध है। सरकार ने यह फैसला ऐसे ही नहीं लिया, बल्कि राज्य के एडवोकेट जनरल की आधिकारिक कानूनी राय लेने के बाद ही आगे कदम बढ़ाया है। राहुल गांधी बिना वजह दखल दे रहे राहुल गांधी के हस्तक्षेप पर नाराजगी जाहिर करते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह कोई राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा नहीं है जिसके लिए देश का विपक्ष का नेता बयानबाजी करे।

अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला, SIR पर विशेष सत्र को तैयार, बोले- वोट बचाने नहीं, घुसपैठियों के लिए थी रैली

करनाल में अमित शाह ने राहुल गांधी पर संसद में हंगामा करने का आरोप लगाया। उन्होंने SIR पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाने और घुसपैठियों को लेकर भी बयान दिया। अमित शाह के नेतृत्व में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' मार्च निकाला गया। राहुल गांधी ने संसद में हंगामा करने को कांग्रेस की कार्यशैली बना दिया है। सरकार SIR के मुद्दे पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार हैं। हरियाणा के करनाल में अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने SIR पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की पेशकश की और INDIA गठबंधन पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कांग्रेस पर



निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने संसद में हंगामा करने को कांग्रेस पार्टी की 'कार्यशैली' बना दिया है। अमित शाह ने राहुल गांधी पर बोला हमला हरियाणा के करनाल में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' मार्च के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए, शाह ने दोहराया कि केंद्र सरकार मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार है। SIR पर विशेष सत्र को तैयार सरकार अमित शाह ने कहा, "राहुल गांधी ने संसद में हंगामा करने को कांग्रेस की कार्यशैली बना दिया है। हम SIR के मुद्दे पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार हैं।" उन्होंने जोर देकर कहा कि घुसपैठियों की पहचान करना और मतदाता सूची से उनके नाम हटाना भाजपा का संकल्प है। 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस' (INDIA) गठबंधन पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा, "उनकी रैली का उद्देश्य वोटों की रक्षा करना नहीं, बल्कि घुसपैठियों को बचाना है।" राहुल गांधी की विदेश यात्राओं के बारे में जानकारी मांगते हुए उन्होंने कहा, आप लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। जनता को यह जानने का अधिकार है। 2014 में SIR कहां था? - अमित शाह पदयात्रा के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "राहुल बाबा, 2014 में SIR कहां था? तब भी आपकी पार्टी पूरी तरह से साफ हो गई थी। 2019 में SIR कहां था? वह चुनाव भी आप हार गए। 2024 में भी कोई SIR नहीं था, फिर भी आप हार गए।

गोकुल में दूध उत्पादकों ने भाजपा को हरा दिया, तो भाजपा ने चुनाव के बाद नियम बदल दिए, राहुल गांधी का बड़ा आरोप



राहुल गांधी ने भाजपा पर गोकुल दूध उत्पादक चुनाव में जनादेश की चोरी का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हार के बाद भाजपा ने नियम बदलकर बहुमत चुराने की कोशिश की। राहुल गांधी ने गोकुल दूध संघ चुनाव को लेकर भाजपा पर आरोप लगाए। गोकुल चुनाव हारने के बाद भाजपा ने जबरन 4 डायरेक्टर बढ़ाए। राहुल गांधी ने पूरी प्रक्रिया को दूध उत्पादकों के वोट की चोरी बताया। कांग्रेस नेता ओर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए राहुल गांधी ने गोकुल दूध उत्पादक संघ के हालिया घटनाक्रम को लेकर केंद्र और राज्य की सत्ताधारी पार्टी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि गोकुल में दूध उत्पादकों ने भाजपा को हरा दिया। तो भाजपा ने चुनाव के बाद नियम बदल दिए।

त्योहार के बीच राजनैतिक रैली से व्यापार को झटका! ट्रेडर्स ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर चिंता जताई



CAIT ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर चिंता व्यक्त की है। संगठन ने देशभर के व्यापारी समुदाय की गहरी पीड़ा और नाराजगी जाहिर की है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का राहुल गांधी को पत्र देश भर के व्यापारी समुदाय की गहरी पीड़ा जाहिर की है। राजनीतिक रैलियों और धरनों के कारण व्यापारिक गतिविधियों में रुकावट आई है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को एक पत्र लिखा है। इसमें संगठन ने देशभर के व्यापारी समुदाय की गहरी पीड़ा और नाराजगी जाहिर की है। उनका आरोप है कि पिछले एक महीने में दिल्ली में राजनीतिक रैलियों, विरोध-प्रदर्शनों और धरनों के कारण व्यापारिक गतिविधियां बार-बार ठप हुई हैं। 1 नवंबर की रैली पर सवाल पत्र में CAIT ने विशेष रूप से 1 नवंबर 2026 को रामलीला मैदान में आयोजित इंडिया गठबंधन की रैली पर सवाल उठाए हैं।

तिरुपति लड्डू में मिलावट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने केस ट्रांसफर करने की मांग खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने लड्डू में मिलावट मामले को लेकर केस को ट्रांसफर करने की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में पहले ही आदेश पारित है। तिरुपति लड्डू में मिलावट के मामले में सुनवाई कोर्ट ने केस ट्रांसफर करने की मांग खारिज की आंध्र प्रदेश से बाहर स्थानांतरित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तिरुपति लड्डू में मिलावट के मामले की सुनवाई को लेकर दायर एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें आंध्र प्रदेश से बाहर किसी पड़ोसी राज्य में मामले को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने स्पष्ट कहा कि सुनवाई स्थानांतरित करने का कोई आधार नहीं बनता है। याचिकाकर्ता की दलील क्या थी? याचिकाकर्ता मच्छिंद्र शांताराम लांके (महाराष्ट्र के एक डेयरी



उद्यमी) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने दलील दी कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री लगातार राजनीतिक बयान दे रहे हैं। इससे राज्य में निष्पक्ष सुनवाई का माहौल प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री लगातार राजनीतिक बयान दे रहे हैं। अभियोजन पक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए। मुकदमे को किसी दूसरे पड़ोसी राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है, जहां यह मुद्दा इतना भावनात्मक न हो। कोर्ट ने क्या कहा? पीठ ने कहा कि इस संबंध में वह पहले ही आदेश पारित कर चुकी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने टिप्पणी की कि हमने अपने आदेश से उन सभी को चुप करा दिया है। अगर कुछ होता है, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। अदालत ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। तिरुपति बालाजी मंदिर का प्रसाद लड्डू करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ा है। कुछ समय पहले लड्डू बनाने में इस्तेमाल घी में मिलावट के आरोप लगे थे। आरोप था कि शुद्ध गाय के घी की जगह नकली या मिलावटी घी इस्तेमाल किया गया। इस विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया। कोर्ट के निर्देश पर जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विशेष जांच दल (SIT) ने जांच की। आरोपियों में सप्लायर कंपनियां और संबंधित लोग शामिल हैं। यह मामला आस्था, मंदिर प्रबंधन और भ्रष्टाचार से जुड़ा होने के कारण संवेदनशील बना हुआ है। सितंबर, 2024 में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी की जांच रिपोर्ट में जानवरों की चर्बी होने की बात सामने आई थी। जिसके बाद पूरे देशभर में इसपर बवाल हुआ था। कई हिंदू संगठन इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गया जिसके बाद एसआईटी गठित की गई।

करनाल में गरजे गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी पर लगाया अराजकता फैलाने का आरोप; कांग्रेस को दी चेतावनी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करनाल में राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर संसद बाधित करने और सड़कों पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाते हुए कड़ी चेतावनी दी। अमित शाह ने राहुल गांधी पर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया करनाल रैली में शाह ने कांग्रेस को कड़ी राजनीतिक चेतावनी दी भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' रैली का पहला चरण पूरा हुआ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। उन्होंने राहुल पर संसद की कार्यवाही में रुकावट डालने और अराजकता फैलाने को लेकर चेतावनी दी। शाह ने कहा कि विपक्ष जहां भी इकट्ठा होना चाहेगा, बीजेपी उन्हें वहीं जवाब देगी। उन्होंने यह बयान हरियाणा में बीजेपी के लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ मार्च को संबोधित करते हुए दिया। हरियाणा के करनाल में बीजेपी द्वारा आज लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ कैंपेन के तहक आखिरी रैली निकाली गई। इसमें केंद्रीय गृह अमित शाह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा नेता स्मृति ईरानी और अन्य लोगों ने भाग लिया। यहां अमित शाह



ने संसदीय लोकतंत्र के प्रति राहुल के नजरिए को लेकर तीखा हमला बोला। संसद का बॉयकॉट करना कांग्रेस का पार्टी कल्चर उन्होंने कहा, प्रजातंत्र में संसद बातचीत का सबसे बड़ा मंच है। फिर भी, राहुल गांधी संसद की कार्यवाही को चलने नहीं देते हैं और नहीं जरूरी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आपने संसद के अंदर हंगामा करना और बॉयकॉट करना कांग्रेस पार्टी का कल्चर बना दिया है। शाह ने कांग्रेस नेता पर संसद के बाहर राजनीतिक टकराव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आप संसद को चलने नहीं दे रहे हैं, इसके बजाय सड़कों पर भीड़ जमा कर रहे हैं और अराजकता फैला रहे हैं, एक अराजकतावादी की तरह काम कर रहे हैं। संसद से लेकर सड़क तक करेंगे विपक्ष का सामना गृह मंत्री ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए आगे कहा, राहुल गांधी, याद रखें, हम सड़कों से आए लोग हैं। बीजेपी संसद, राज्य विधानसभाओं, गांवों, खेतों और सड़कों पर विपक्ष का सामना करेगी। उन्होंने कहा, और अगर आप भीड़ जमा करने पर अड़े रहे, तो भाजपा के कार्यकर्ता वहां पर भी आपको मुंहतोड़ जवाब देंगे। PM मोदी को मिला जनता का भरपूर समर्थन अमित शाह ने यह भी कहा कि यह रैली कैंपेन के पहले फेज का समापन है, जो 22 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच देश भर में बीजेपी मुख्यालयों पर किया गया था। उन्होंने दावा किया कि पार्टी ने कैंपेन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जनता का बहुत ज्यादा उत्साह और समर्थन देखा है। संसद में आकर चर्चा करे विपक्षः अमित शाह अगर आप एक जिम्मेदारी से चर्चा करना चाहते हो, अगर आपके मुद्दों में सच्चाई है, आपके मुद्दों में दम है, तो संसद में चर्चा करिए।

दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में बड़ा हादसा, तीन मंजिला इमारत ढही; 2 लोगों की मौत, कई मलबे में दबे

दिल्ली के चावड़ी बाजार में गुरुवार सुबह निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत ढह गई। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है, राहत अभियान जारी है। दिल्ली के चावड़ी बाजार में निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत अचानक ढह गई 2 लोगों की मौत, कई मलबे में फंसे दमकल विभाग की छह गाड़ियां राहत और बचाव अभियान में जुटीं दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहां गली शाहतारा स्थित शीश महल में एक निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत अचानक ढह गई। हादसे में अब तक दो लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंच गए। दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) के मुताबिक, इमारत ढहने की सूचना सुबह करीब 9:50 बजे मिली थी। घटनास्थल चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के सामने स्थित है।



सूचना मिलने के तुरंत बाद दमकल की छह गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इमारत निर्माणाधीन थी। मलबे में कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त दमकल गाड़ियों और अधिकारियों को भी घटनास्थल पर भेजा गया है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, दमकल की कम से कम छह गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। दमकल कर्मी मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान चला रहे है। हादसे में में अब तक दो लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है। जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। चावड़ी बाजार पुरानी दिल्ली के सबसे व्यस्त और घनी आबादी वाले इलाकों में शामिल है। यहां बड़ी संख्या में दुकानें और पुरानी इमारतें मौजूद हैं। इलाके में कई इमारतें एक-दूसरे से सटी हुई हैं। ऐसे में निर्माणाधीन इमारत के ढहने के बाद आसपास की इमारतों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। सौरभ भारद्वाज ने रेखा सरकार पर बोला हमला हादसे के बाद आम आदमी पार्टी (आप) नेता सौरभ भारद्वाज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा चावड़ी बाजार में एक और 3 मंजिला इमारत गिर गई। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। रेखा गुप्ता की सरकार और MCD ने दिल्ली की सभी इमारतों का कई बार सुरक्षा ऑडिट किया, फिर भी इमारतें गिरती रहती हैं। क्यों? आप नेता ने आगे कहा कि सुरक्षा ऑडिट के आदेश बार-बार दिए गए, लेकिन असली एक्शन लेने के बजाय, कई विभागों ने कई बार रिश्वत ली, जिसकी वजह से हर महीने इमारतें गिरती हैं। पहले केवल दिल्ली पुलिस और MCD ही रिश्वत लेती थी। रेखा गुप्ता की सरकार आने के बाद दमकल विभाग और SDMs (उनके अंडर रेवेन्यू डिपार्टमेंट) ने भी बिल्डिंग्स से रिश्वत लेना शुरू कर दिया।

राजघाट पर धरना दे रहे अंकिता के माता-पिता को पुलिस ने हटाया, मां की बिगड़ी तबीयत



अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग कर रहे उसके माता-पिता को दिल्ली पुलिस ने राजघाट से हटा दिया। धरना प्रदर्शन के दौरान अंकिता की मां की तबीयत बिगड़ गई। अंकिता के माता-पिता राजघाट पर मौन व्रत रखकर न्याय मांग रहे थे दिल्ली पुलिस ने बार-बार अनुरोध के बाद उन्हें मौके से हटाया मां सोनी देवी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें बुराड़ी अस्पताल ले जाया गया उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग कर रहे उसके माता-पिता को दिल्ली में राजघाट के मुख्य गेट के पास से हटा दिया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, राजघाट धरना प्रदर्शन के लिए निर्धारित जगह नहीं है। पुलिस ने अंकिता के माता-पिता से कई बार वहां से जाने का अनुरोध किया, लेकिन उनके नहीं हटने पर उन्हें मौके से हटाया गया। सूत्रों के मुताबिक, अंकिता भंडारी के माता-पिता बुधवार को प्रार्थना करने और मीडिया से बातचीत करने के लिए राजघाट पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने दो अन्य लोगों के साथ राजघाट के मुख्य द्वार के पास धरना शुरू कर दिया।

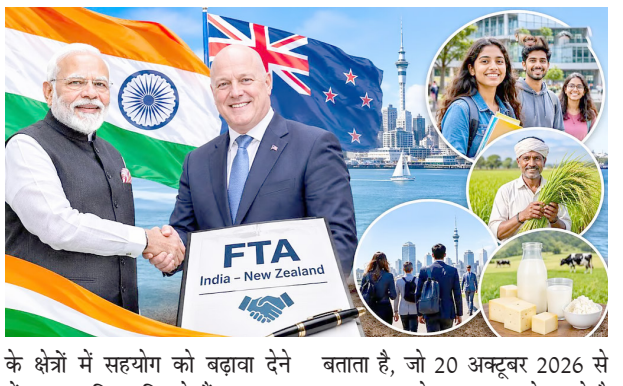
मछुआरों को बचाने गई SDRF की नावें हुई थीं लापता, NDRF ने सुबह 5:30 बजे सभी को सुरक्षित निकाला



तेलंगाना के खम्मम की बेथुपल्ली झील में लापता मछुआरों और SDRF कर्मियों को NDRF ने सुरक्षित बचा लिया। सुबह 5:30 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ और कोई हताहत नहीं हुआ। तेलंगाना में मछुआरों को बचाने के लिए तैनात SDRF की एक नाव पलट गई। इस घटना के बाद SDRF के 11 जवान लापता हो गए। तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने बेथुपल्ली झील से SDRF नावों के लापता होने के बारे में जानकारी ली। ऐसी खबरें सामने आईं कि तेलंगाना में मछुआरों को बचाने के लिए तैनात SDRF की एक नाव पलट गई। शुरुआत में बताया गया था कि इस घटना के बाद SDRF के 11 जवान लापता हैं। अब इस मामले में एक अहम जानकारी सामने आई है। तेलंगाना के खम्मम जिले में बुधवार को बेथुपल्ली टैंक के ओवरफ्लो होने के बाद, वहां फंसे मछुआरों को बचाने की कोशिश में दो बचाव नौकाएं पलट गईं थी।

न्यूजीलैंड में नौकरी और पढ़ाई का नया रास्ता, भारत के साथ FTA लागू; जानें छात्रों और युवाओं को क्या मिलेगा

भारत-न्यूजीलैंड FTA अक्टूबर 2026 से लागू हो गया है। भारतीय निर्यात पर जीरो ड्यूटी, 5,000 वर्क वीजा, 20 अरब डॉलर निवेश और किसानों के लिए क्या हैं प्रावधान? भारत-न्यूजीलैंड के बीच FTA समझौता 20 अक्टूबर 2026 से लागू हुआ। न्यूजीलैंड ने 100% भारतीय निर्यात पर करों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। FTA समझौते से व्यापारी 1.4 अरब ग्राहकों तक अपनी पहुंच बना सकेंगे। जब भारत और न्यूजीलैंड की बात आती है, तो सबसे पहले क्रिकेट का खयाल आता है। हालांकि, इन दोनों देशों के बीच एक और अहम संबंध भी है जो उनकी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि, दोनों देशों के बीच राजनीतिक, व्यापारिक और शैक्षणिक समझौते भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये समझौते व्यापार और शिक्षा



के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। अक्टूबर 2026 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता हुआ। हालांकि बातचीत काफी पहले शुरू हो गई थी, लेकिन यह समझौता 20 अक्टूबर 2026 से लागू हुआ। भारत-न्यूजीलैंड FTA क्या है? भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के बारे में बताता है, जो 20 अक्टूबर 2026 से लागू हुआ। तो आइए आपको बताते है कि मुक्त व्यापार समझौता क्या है, यह कैसे काम करता है, और इसका दोनों देशों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुक्त व्यापार समझौता (FTA) क्या है? आमतौर पर, जब कोई देश दूसरे देश को सामान बेचता है, तो सामान मंगाने वाला देश कुछ अतिरिक्त कर लगाता है, जिन्हें 'टैरिफ' (Tariffs) कहा जाता है। मुक्त व्यापार समझौता दो देशों के बीच एक आधिकारिक अनुबंध होता है, जिसका उद्देश्य इन अतिरिक्त करों को कम करना या हटाना है, ताकि दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार करना तथा श्रमिकों का आना-जाना आसान और सस्ता हो सके। इस समझौते के लिए औपचारिक बातचीत 16 मार्च 2025 को भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैक्ले के बीच शुरू हुई।

बातचीत फिर से शुरू होने के बाद, दोनों देशों ने केवल 6 महीनों में इस समझौते को अंतिम रूप दे दिया, और 19 महीने बाद यह लागू हो गया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार की स्थिति व्यापार की मात्राः भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में 1 बिलियन डॉलर को पार कर गया था।

सम्पादकीय

नेतन्याहू की जीत या हार ?

इस समय इजरायल की राजनीति में एक अजीब विरोधाभास देखने को मिल रहा है। क्या नेतन्याहू फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? वहां लोकतंत्र, फिलिस्तीनी जनता का अस्तित्व, अंतरराष्ट्रीय कानून की विश्वसनीयता और पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन, सभी की परीक्षा हो रही है। बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाला दक्षिणपंथी गठबंधन आम चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल करने में विफल रहा। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र जांच आयोग ने गाजा में सैन्य अभियानों और युद्धविराम के बाद भी जारी कथित अत्याचारों के संबंध में बेहद गंभीर निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। हालांकि राजनीतिक स्तर पर नेतन्याहू की पकड़ कमजोर हो रही है, लेकिन सैन्य और रणनीतिक स्तर पर इजरायल की आक्रामक भूमिका बनी हुई है। इससे कई सवाल उठते हैं। इस लिहाज से पिछले महीने इज़राइल में हुए चुनाव काफ़ी अहम थे। 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के हमले के बाद ये पहले आम चुनाव थे। इसलिए ये महज़ सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि नेतन्याहू के नेतृत्व पर जनता का मत था। हमास के हमले को रोकने में नाकामयाबी, उसके बाद गाज़ा में चला लंबा युद्ध, ईरान के साथ सैन्य संघर्ष और इज़राइल का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गतिरोध, इन सभी ने स्वाभाविक रूप से मतदाताओं के फ़ैसलों को प्रभावित किया। नेतन्याहू की लिकुद पार्टी ने चुनाव में 26 सीटें जीतीं। उनके दक्षिणपंथी और धार्मिक दलों के गठबंधन को कुल 53 सीटें मिलीं। वे बहुमत के लिए आवश्यक 61 सीटों तक नहीं पहुंच सके। पूर्व सेना प्रमुख गादी आइज़ेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन ने 48 सीटें जीतीं, जबकि अरब दलों ने 19 सीटों के साथ एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस परिणाम ने इजरायली राजनीति को तीन गुटों में बांट दिया है। हालांकि नेतन्याहू हार गए हैं, लेकिन विपक्ष निर्णायक जीत हासिल करने में सक्षम नहीं हो पाया है। सबसे अहम मुद्दा अरब पार्टियों की बढ़ती ताकत है। इज़राइल की आबादी में अरब नागरिकों की संख्या लगभग 20 प्रतिशत है। हालांकि, देश के शासन में ऐतिहासिक रूप से उनकी भूमिका गौण रही है। इस चुनाव में जॉइंट लिस्ट और राआम पार्टियों द्वारा जीती गई 19 सीटों ने सरकार गठन की प्रक्रिया में उनकी भूमिका को निर्णायक बना दिया है। विपक्ष को नेतन्याहू को रोकने के लिए अरब पार्टियों के समर्थन की ज़रूरत है; लेकिन विपक्षी खेमे की कुछ पार्टियां अरब राजनीतिक ताकतों के साथ सहयोग करने के खिलाफ हैं। नतीजों से यह साफ हो गया है कि नेतन्याहू के खिलाफ राजनीतिक एकता और अरब पार्टियों के साथ सत्ता में आने की तत्परता दो अलग-अलग बातें हैं। यही नेतन्याहू की राजनीतिक ताकत है। हालांकि उनका गठबंधन बहुमत से काफी दूर है, लेकिन विपक्ष के बीच वैचारिक मतभेद उन्हें सत्ता की दौड़ में बनाए रख सकते हैं। उनके पास राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने, कुछ विपक्षी सांसदों को अपने पक्ष में करने या फिर से चुनाव जीतने की स्थिति पैदा करने के विकल्प हैं। दूसरे शब्दों में, मतदाताओं ने उन्हें निर्विवाद जनादेश नहीं दिया है; लेकिन उन्हें राजनीतिक मैदान से बाहर भी नहीं किया गया है। हालांकि, इजरायली राजनीति में सत्ता संघर्ष को समझने के लिए गाजा में हुई मानवीय त्रासदी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग द्वारा 26 अक्टूबर, 2026 को प्रस्तुत रिपोर्ट इजरायल की सैन्य नीतियों पर गंभीर सवाल उठाती है। आयोग का निष्कर्ष है कि अक्टूबर 2025 में युद्धविराम लागू होने के बाद भी गाजा में इजरायली अधिकारियों और बलों द्वारा नरसंहार के कृत्य जारी रहे। रिपोर्ट का एक और चौंकाने वाला पहलू युद्धविराम के बाद भी गाजावासियों की सुरक्षा की कमी है। आयोग का कहना है कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सैन्य अभियान, ड्रोन और क्वाडकॉप्टर का उपयोग, तोप के गोले और स्नाइपर हमले उन्हें लगातार खतरा पहुंचा रहे हैं। भले ही कागजों पर युद्ध समाप्त हो गया हो, लेकिन आम नागरिकों के दिलों में युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। वेस्ट बैंक की स्थिति दर्शाती है कि युद्ध का दायरा गाजा तक सीमित नहीं है। आयोग का आरोप है कि इजरायली सैन्य अभियानों और यहूदी बस्तियों द्वारा की गई हिंसा के कारण फिलिस्तीनी नागरिकों का विस्थापन, हत्याएं और मानवाधिकार उल्लंघन हो रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार, फिलिस्तीन में लगभग 75,000 लोग मारे गए हैं। इनमें 21,500 बच्चे और 11,000 महिलाएं शामिल हैं। यह एक बेहद क्रूर नरसंहार है। भारतीय मूल के पूर्व न्यायाधीश श्रीनिवासन मुरलीधर की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग ने इजरायल की कार्रवाइयों को अलग-थलग घटनाओं के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यापक नीति के हिस्से के रूप में देखा। आयोग ने इन घटनाओं के आपसी संबंध पर प्रकाश डाला, जिनमें घरों को ध्वस्त करना, नागरिकों की हत्या करना, उन्हें उनकी जमीनों से विस्थापित करना और उनके जीवनयापन के बुनियादी साधनों को नष्ट करना शामिल है। हालांकि, इज़राइल ने इन आरोपों का खंडन किया है। इज़राइली प्रतिनिधियों का तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट इज़राइल की छवि धूमिल करने और देश के अस्तित्व को ही अपराध घोषित करने का प्रयास है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि इज़राइल को अपने नागरिकों की रक्षा करने का अधिकार है। इज़राइल की सुरक्षा का मुद्दा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। हमास द्वारा 7 अक्टूबर को किया गया हमला, नागरिकों की हत्या और बंधकों का मुद्दा अनदेखा नहीं किया जा सकता। हमास के आतंकवादी कृत्यों को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन आतंकवाद से लड़ते हुए पूरी नागरिक आबादी को इसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर करना अंतरराष्ट्रीय कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।

खुद को कमजोर करने वाली राजनीति

हाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के एक कार्यक्रम में कहा कि अपनी नकारात्मक राजनीति के चलते कांग्रेस अगले 30 वर्षों तक केंद्र की सत्ता में वापस नहीं आ सकती। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस की आलोचना की, लेकिन उनका कोई शब्द अमर्यादित या अपमानजनक नहीं था। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पटना के एक कार्यक्रम में अपने एक कार्यकर्ता के टोकने पर गुस्से में कहा, 'मोदी का बाप भी जाएगा...।' प्रसंग यह था कि जब उन्होंने कहा कि मोदी जेल जाएंगे तो उक्त कार्यकर्ता ने टिप्पणी की कि मोदी तब तक कहीं नहीं जाने वाले, जब तक उनके खिलाफ बगावत नहीं होगी। खरगे जैसे वरिष्ठ नेता की भाषा से पार्टी के राजनीतिक सोच पर सवाल उठते हैं। दुख की बात यह रही कि कांग्रेस के किसी नेता ने इस बयान पर खेद नहीं जताया, बल्कि उसके बचाव में तर्क दिए। संसदीय लोकतंत्र में नेता अपने राजनीतिक विरोधियों की आलोचना करते हैं, उन पर हमला बोलते हैं और अभियान चलाते हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा नहीं लांघते और न ही उनके परिवार तक जाते हैं। किसी भी दल को चुनाव जीतने के लिए संगठन मजबूत करने और जनता का विश्वास जीतने की जरूरत होती है। इसके लिए जनहित के मुद्दे उठाने, सकारात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत करने और नेतृत्व की ऐसी छवि बनाने की आवश्यकता होती है, जिससे मतदाताओं को लगे कि उसके नेतृत्व में देश अधिक सुरक्षित रहेगा। कांग्रेस की रणनीति इससे अलग दिखाई देती है। चुनावों में हार-जीत होती रहती है। जनसंघ की स्थापना से लेकर सत्ता तक पहुंचने के लिए भाजपा को अपनी विचारधारा और कार्यशैली के आधार पर लंबा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन चुनावी हार के बाद उसने सत्तापक्ष के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने या चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा पर हमला करने का अभियान नहीं चलाया, लेकिन राहुल और उनके साथी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वह पहले कभी नहीं देखी गई। कांग्रेस की समस्या यह है कि उसने 2014 से अब तक अपनी चुनावी हार का ईमानदारी से विश्लेषण नहीं किया। विश्लेषण से संगठन, नीति, नेतृत्व, रणनीति और वक्तव्यों की कमजोरियां सामने आतीं और उन्हें दूर करने की कोशिश हो सकती थी। कांग्रेस के अनुभवी और विवेकशील नेता राहुल और उनके करीबियों द्वारा किनारे कर दिए गए हैं या वे स्वयं हाशिए पर पहुंच गए हैं। आज राहुल के रणनीतिकार और सलाहकार वामपंथी, समाजवादी, एनजीओ और इस्लामवादी विचारधारा से जुड़े देश-विदेश के लोग हैं। हाल में दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के घर हुई माक संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ लाए गए जन महाभियोग में राहुल के साथ योगेंद्र यादव, नेहा बोरा भी दिखाई दिए। जनता से संवाद पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन माक पार्लियामेंट जैसे आयोजन तो वामपंथी तथा एनजीओ की कार्यशैली का हिस्सा रहे हैं। एक समय दुनिया भर में कम्युनिस्ट नेता सरकारों और संपन्न वर्ग के खिलाफ लोगों में असंतोष पैदा कर हिंसा और उथल-पुथल के जरिये सत्ता हासिल करने की कोशिश करते थे। राहुल गांधी संसदीय राजनीति करते हुए वैसी ही स्थिति पैदा करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। वे कभी 'चौकीदार चोर है' का नारा लगवाते हैं तो कभी ईवीएम, एसआइआर और वोट चोरी का मुद्दा भाषा की मर्यादा की अनदेखी कर उठाते हैं। वे और उनके सहयोगी इन मुद्दों को जिस रूप में पेश करते हैं, जमीनी स्तर पर वैसी स्थिति दिखाई नहीं देती। वैचारिक स्पष्टता के अभाव में चुनावी हार से नाराज होकर वे और उनके साथी मर्यादा की सीमा लांघते हैं। लगता है कांग्रेस में मोदी, भाजपा या आरएसएस के विरुद्ध जो जितनी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेगा, उसे उतना ही अधिक महत्व मिलेगा। स्वयं राहुल ने 2019 के चुनाव से पहले कहा था कि कुछ दिनों में मोदी बाहर निकलेगा तो लोग डंडों से उसकी पिटाई करेंगे। अब वे कह रहे हैं कि मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार को जेल जाना होगा। ऐसे बयानों की लंबी श्रृंखला है। खरगे प्रधानमंत्री को रावण, जहरीला नाग आदि कह चुके हैं। पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री के पिता का नाम लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। निःसंदेह भाजपा से भी गलतियां होती हैं। उम्मीदवारों के चयन, मुद्दों और जातीय समीकरणों के मामले में उससे गलतियां हुई हैं। लोकसभा चुनाव में कई राज्यों में उसे झटका लगा, लेकिन उसने हार का विश्लेषण किया, सुधार किए और कई विधानसभा चुनावों में सफलता हासिल की। दलों में अपनी गलतियों के परिणाम भुगतने के बाद अपनी कमजोरियों का विश्लेषण कर बदलाव करने का साहस होना चाहिए। हार का दोष विरोधियों या संवैधानिक संस्थाओं पर मढ़ने से किसी पार्टी की स्थिति नहीं बदल सकती, लेकिन राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस मध्यमार्ग छोड़कर अति वामपंथ की ओर बढ़ चुकी है। हालांकि भाजपा के मजबूत रहने तक ऐसी स्थिति पैदा करना संभव नहीं होगा, जिसमें राहुल प्रधानमंत्री के विरुद्ध चोर, देशद्रोही जैसे अपशब्दों का इस्तेमाल कर और चुनाव आयोग एवं अन्य संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ माहौल बनाकर वामपंथी और एनजीओ शैली में लोगों के बीच असंतोष एवं विद्रोह पैदा कर सकें।

कठिन हुई ट्रंप की राह

अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को जोरदार झटका लगा। उनकी प्रतिद्वंद्वी डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस के दोनों सदनों- प्रतिनिधि सभा एवं सीनेट में बहुमत के पड़ाव पर पहुंच गई है। चुनाव परिणाम ट्रंप प्रशासन को पारंपरिक आईना दिखाने से अधिक कड़ी फटकार लगाने जैसे हैं। इन नतीजों की गूंज कहीं गहरे संदेश समाहित किए हुए है। ट्रंप की मनमानी टैरिफ नीतियों से बढ़ी महंगाई से जीवन-यापन की लागत में बढ़ोतरी से आम अमेरिकी त्रस्त हो गए थे। ईरान के साथ युद्ध भी घरेलू बेचैनी को बढ़ाने वाला साबित हुआ। मध्यावधि चुनाव में लगे झटके के बाद ट्रंप को अपने शेष कार्यकाल के लिए नए सिरे से रणनीति तैयार करनी होगी, क्योंकि अब उनकी राजनीतिक चुनौतियों का बढ़ना तय है। अमेरिकी संसद पर डेमोक्रेट का नियंत्रण ट्रंप के घरेलू एजेंडे की डोर को कमजोर करेगा। इससे कराधान, सरकारी खर्च की अनुमति पर तकरार से लेकर विधायी कदमों पर टकराव बढ़ने के आसार बनेंगे। हालांकि ट्रंप के पास टैरिफ, स्वास्थ्य सेवा और आव्रजन संबंधी अपनी नीतियों के मामले में कार्यकारी अधिकारों एवं वीटो की शक्ति होगी, लेकिन संस्थागत द्वंद्व बढ़ने की स्थिति में राष्ट्रपति को किसी ठोस विधायी व्यवस्था के बजाय अस्थायी वित्तीय प्रविधानों से ही काम चलाना पड़ेगा। ट्रंप प्रशासन के लिए संसदीय कसौटियां भी सख्त होंगी, जिसमें कार्यकारी शक्तियों के दुरुपयोग, नैतिक सरोकारों और विदेशी व्यावसायिक हितों पर बारीक नजर रखी जाएगी, जबकि सीनेट में डेमोक्रेटिक बहुमत न्यायिक और कैबिनेट स्तर की नियुक्तियों की राह और जटिल बनाएगा। अपने शेष कार्यकाल में ट्रंप को अपनी प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के बजाय अपने तमाम फैसलों के बचाव में ही अपनी अधिकांश राजनीतिक पूंजी झोंकनी होगी। इतिहास साक्षी है कि जब भी अमेरिकी राष्ट्रपतियों को घरेलू मोर्चे पर विधायी विरोध के चलते कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो उन्होंने विदेश नीति में अधिक रणनीतिक गुंजाइश तलाशने की कोशिश की है, क्योंकि इस मोर्चे पर उनकी कार्यकारी शक्तियां कहीं व्यापक होती हैं। ट्रंप भी इसी राह पर बढ़ सकते हैं, लेकिन ईरान से संघर्ष और पश्चिम एशिया की अस्थिरता उनकी विदेश नीति को भी मुकाबले का एक नया अखाड़ा बना सकती है। संसद पर डेमोक्रेटिक नियंत्रण के चलते सैन्य अभियानों, उनके वित्तीय बोझ और सामरिक उद्देश्यों की कहीं अधिक सख्त निगरानी के आसार बढ़ेंगे। इसके अलावा मुद्रास्फीति की चिंताओं के बीच टैरिफ से जुड़ी शक्तियों के एकतरफा इस्तेमाल पर भी ट्रंप प्रशासन को कड़ी चुनौती मिलेगी। अमेरिका के सहयोगियों से लेकर प्रतिद्वंद्वियों तक के लिए मध्यावधि चुनावों के परिणाम मायने रखते हैं। बदले राजनीतिक परिदृश्य में अमेरिकी नीति-निर्माण में अस्थिरता गहराने का अंदेशा है। कार्यकारी शक्ति के रूप में ट्रंप प्रशासन के पास विदेश मामलों पर निर्णय के विशेषाधिकार तो कायम रहेंगे, लेकिन संसदीय गतिरोध से उनका प्रभाव अवश्य प्रभावित होगा। अमेरिका के विरोधी देश इसका लाभ उठाने की गुंजाइश तलाशेंगे। खास तौर से वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए यह स्थिति और संवेदनशील होगी, जहां ईरान संघर्ष, प्रतिबंधों की नीति और सैन्य भागीदारी पर संसद की कड़ी निगरानी का मिलाजुला असर कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता बढ़ा सकता है, जिसका व्यापक प्रभाव वैश्विक मुद्रास्फीति पर पड़ेगा। यूरोपीय सहयोगियों के साथ ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र के सहयोगी देशों के लिए डेमोक्रेट्स की बढ़ी शक्ति संवाद का एक वैकल्पिक माध्यम और अमेरिकी सुरक्षा में एकतरफा कटौती के सापेक्ष कुछ हद तक भरोसा प्रदान कर सकती है, फिर भी अपने सुरक्षा दायित्वों का बोझ सहयोगी देशों को मुख्य रूप से स्वयं ही उठाना पड़ेगा। भारत के लिए भी अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के नतीजे गहरे अर्थ लिए हुए हैं। भले ही दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी एक बड़ी हद तक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर टिकी हो, लेकिन वाशिंगटन में बदले राजनीतिक समीकरण विशेष नीतिगत क्षेत्रों में नए अवसर बना सकते हैं। इसी के साथ जहां डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत व्यापार वार्ताओं की राह को और जटिल बना सकती है, वहीं घरेलू राजनीतिक आलोचनाओं से निपटने के उद्देश्य से ट्रंप ठोस आर्थिक परिणाम दिखाने के लिए व्यापार समझौते को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। एकतरफा टैरिफ को लेकर संसद की निगरानी भी नई दिल्ली के लिए सौदेबाजी की ताकत बढ़ाएगी, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में, जहां अमेरिकी बाजार तक पहुंच व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद भी यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि संसद पर डेमोक्रेटिक नियंत्रण से अमेरिकी व्यापार नीतियां स्वाभाविक रूप से भारत के प्रति लचीली हो जाएंगी। वर्तमान में बाजार तक पहुंच, घरेलू उद्योग संरक्षण और व्यापार असंतुलन से जुड़े मुद्दे केवल रिपब्लिकन पार्टी तक सीमित नहीं रह गए हैं। आव्रजन भी एक ऐसा क्षेत्र है, जहां संसद में बदला हुआ शक्ति-संतुलन भारत के लिए काफी मायने रख सकता है। रूसी कच्चे तेल की निरंतर खरीद का मुद्दा भी द्विपक्षीय संबंधों में तनाव और मतभेद का एक पहलू बना रहेगा। मध्यावधि चुनावों ने ट्रंप के शेष कार्यकाल में राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ाने का काम किया है। विधायी प्रतिरोध उनके घरेलू एजेंडे को सीमित करने के साथ विदेश नीति से जुड़े उनके लक्ष्यों की पूर्ति को जटिल बना सकते हैं। यह जनादेश हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर अमेरिकी विदेश नीति पर दोनों दलों के नजरिये की बुनियाद को बदले बिना ट्रंप की अतिशय महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगा सकता है।

पत्नी के प्यार में दीवाने हुए सांसद मनोज तिवारी, बनारस में चलाया रिक्शा; घुटनों पर बैठ किया प्रपोज

मनोज तिवारी ने पत्नी सुरभि को खास डेट पर ले जाने के लिए बनारस की गलियों में कई काम किए। इसके बाद घुटनों पर बैठकर उन्हें प्रपोज किया, जिसे देखकर सभी भावुक हो गए। मनोज तिवारी ने बनारस की गलियों में चलाया रिक्शा, बेची साड़ियां घुटनों पर बैठकर पत्नी सुरभि को किया रोमांटिक प्रपोज पति के प्यार भरे अंदाज पर इमोशनल हुईं सुरभि, गले लगकर रोईं कलर्स टीवी के रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में सांसद मनोज तिवारी अपनी पत्नी सुरभि तिवारी के साथ नजर आ रहे हैं। इस शो में मनोज तिवारी का सबसे अनोखा अंदाज देखने के लिए मिलने वाला है। पति पत्नी और पंगा में सांसद मनोज तिवारी अपनी पत्नी के साथ बनारस की गलियों में घुमते हुए देखे जा सकते है। शो के लेटेस्ट प्रोमो में वो अपनी पत्नी को डेट पर ले जाने के लिए वेटर



का काम करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही उन्होंने घुटनों पर बैठकर अपनी पत्नी को प्रपोज भी किया। बनारस की गलियों में मनोज तिवारी ने चलाया रिक्शा जियो हॉटस्टार पर पति पत्नी और पंगा के लेटेस्ट प्रोमो में सांसद और भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी को बनारस की गलियों में एक अजब-गजब टास्क पूरा करने का मौका मिला है। जिसमें उन्हें अपनी पत्नी के लिए मेहनत से रुपये कमाने है। इस प्रोमो में मनोज तिवारी को पत्नी को डेट पर ले जाने के लिए रेस्टॉरेंट में वेटर का काम करते हुए, रिक्षा चलाते हुए और बनारसी साड़ियां बेचते हुए देखने के लिए मिला है। घुटने पर बैठकर किया प्रपोज पति पत्नी और पंगा के इस एपिसोड में मनोज तिवारी का रोमांटिक अंदाज सामने आने वाला है। इस प्रोमो वीडियो में वो अपनी पत्नी सुरभि तिवारी को बोट राइड के लिए लेकर जाते है। साथ ही इस वीडियो में मनोज सुरभि को बाइक राइड डेट पर भी लेकर जाते हुए दिखायी देते है। हालांकि इस प्रोमो का सबसे खास हिस्सा वो है, जब मनोज तिवारी घुटनों पर बैठकर अपनी पत्नी को प्रपोज करते हैं। सुरभि तिवारी हुई इमोशनल मनोज तिवारी के घुटनों पर बैठकर प्रपोज करने के बाद उनकी पत्नी काफी इमोशनल हो जाती हैं। मनोज तिवारी अपनी पत्नी को आय लव यू भी कहते हैं और साथ ही ये भी कहते है कि तुम बहुत अच्छी हो। अपने पति के मुंह से ये प्यार भरी बातें सुनकर सुरभि खुद को रोक नहीं पाती और वो मनोज तिवारी के गले लगकर रोने लगती है। फैंस ने की मनोज-सुरभि की तारीफ सोशल मीडिया पर भी मनोज तिवारी और सुरभि का यह वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। फैंस दोनों की जोड़ी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। किसी ने उन्हें क्यूट कपल बताया, तो किसी ने मनोज तिवारी को शो की जान कहा।

फूट-फूटकर रोई भोजपुरी एक्ट्रेस, क्या अरिश्फा आम्रपाली के लिए देगी अपनी लाइफलाइन की कुर्बानी



बिग बॉस 20 के फैमिली मैसेज टास्क में आम्रपाली दुबे अपने पिता की आवाज सुनकर भावुक हो गईं। वहीं, माही विज के अरिश्फा के कैसेट तोड़ने के फैसले से उसका दिल टूट गया है। पिता की आवाज सुनकर फूट-फूटकर रोईं आम्रपाली दुबे अरिश्फा के हाथ में आम्रपाली का फैमिली मैसेज सुनने का फैसला फैमिली टास्क के बीच अरिश्फा खान बनीं बिग बॉस की नई कैप्टन कलर्स टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस में ये हफ्ता काफी इमोशनल होने वाला है। जहां शो में सभी कंटेस्टेंट्स को उनके परिवार वालों का मैसेज सुनने का मौका मिलने वाला है। हालांकि ये टास्क इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस टास्क में घर के सभी सदस्यों को सामने वाले कंटेस्टेंट के लिए अपनी एक लाइफ गंवानी होगी। बिग बॉस में इस हफ्ते संदेशें आते है टास्क देखने के लिए मिलने वाला है। इस टास्क में सभी कंटेस्टेंट्स को उनके घरवालों के ऑडियो मैसेज सुनने का मौका मिल सकता है।

रामायण मूवी रिलीज के बीच सनी देओल को सतायी धर्मेंद्रजी की याद, छोटे बेटे संग पहुंचे पापा के फार्महाउस

सनी देओल अपने पिता धर्मेंद्र की याद में लोनावला स्थित उनके फार्महाउस पहुंचे। अभिनेता ने बेटे राजवीर के साथ एक भावुक वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा- मिसिंग यू पापा। पापा धर्मेंद्र की याद में फार्महाउस पहुंचे सनी देओल बेटे राजवीर के साथ शेयर किया इमोशनल वीडियो, लिखा- मिसिंग यू पापा लोनावला की पहाड़ियों में 100 एकड़ में फैला है धर्मेंद्र का फार्महाउस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गदर मचाने वाले सनी देओल हाल ही में फिल्म रामायण में हनुमान का किरदार निभाते हुए देखे जाने वाले है। साथ ही उनकी फिल्म सूर्याः आरंभ से अंत भी जल्द दस्तक देने वाली है। रामायण रिलीज के समय जहां फैंस सनी देओल को बतौर हनुमान बड़े पर्दे पर देखने के लिए एक्साइटेड है, तो वहीं सनी देओल को अपने पापा की याद सता रही है। टफ बॉडी वाले सनी देओल के पीछे एक वो बेटा भी छिपा है, जो अपने पापा से काफी प्यार करता हैं। सनी देओल पहुंचे पापा के फार्महाउस सनी देओल ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक



स्पेशल वीडियो शेयर की है। इस वीडियो में सनी देओल के साथ उनके छोटे बेटे राजवीर देओल भी नजर आ रहे हैं। सनी देओल अपने पापा की याद में धर्मेंद्रजी के फार्महाउस पहुंच गए हैं। इस वीडियो में सनी देओल ने उनकी और धर्मेंद्र की फिल्म अपने का टाइटल ट्रैक जोड़ा है। इस वीडियो के कैप्शन में सनी ने लिखा है कि मिसिंग यू पापा। लोनावला में स्थित है धर्मेंद्रजी का फार्महाउस दरअसल, धर्मेंद्र का यह फार्महाउस महाराष्ट्र की लोनावला और खंडाला की पहाड़ियों के बीच स्थित है। मुंबई के फिल्मी माहौल और भागदौड़ से दूर करीब 100 एकड़ में फैली इस संपत्ति को धर्मेंद्र अपना सुकून भरा ठिकाना मानते थे। यहां वह शूटिंग और फिल्मों की व्यस्तता से दूर परिवार के साथ समय बिताते थे। इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल उन्हें काफी पसंद था। फार्महाउस की बनावट भी इसे खास बनाती है। यहां लकड़ी और पत्थरों से बने हिस्से इसे गांव के घर जैसा रूप देते हैं। धर्मेंद्र को यहां खेती करना और अपने हाथों से फल-सब्जियां उगाना पसंद था। वह कई बार सोशल मीडिया पर इस फार्महाउस के वीडियो भी साझा करते थे, जिनमें उनकी सादगी और प्रकृति के प्रति लगाव देखने को मिलता था। उनके इन वीडियो में कभी खेतों की हरियाली तो कभी वहां उगाई गई सब्जियों की झलक दिखाई देती थी। अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को 89 वर्ष की उम्र में मुंबई स्थित उनके घर पर निधन हो गया था।

सुरेश रैना फिर लौटेंगे चेन्नई सुपर किंग्स? CSK से खुद मांगी ये बड़ी जिम्मेदारी



सुरेश रैना ने चेन्नई सुपर किंग्स के कोचिंग स्टाफ से जुड़ने की इच्छा जताई है। अश्विन के यूट्यूब चैनल पर रैना ने खुलासा किया कि उन्होंने फ्रेंचाइजी से कोचिंग की जिम्मेदारी मांगी है। सुरेश रैना एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़ने को बेताब हैं। रैना साल 2008 से 2021 तक लगातार CSK टीम का मुख्य हिस्सा रहे। रैना आज भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। न्नई सुपर किंग्स (CSK) के दिग्गज और पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना एक बार फिर पिली जर्सी के साथ जुड़ने को बेताब हैं।

125 की स्पीड से 140 तक का सफर, मैनचेस्टर में फ्लॉप होने वाले अंशुल कंबोज ने ऑकलैंड में कैसे मचाया तहलका?

भारतीय तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड वनडे में अपनी रफ्तार और सटीक लाइन-लेंथ से तहलका मचा दिया है। आइए जानते है उनकी गेंदबाजी के सफलता के राज। अंशुल कंबोज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड वनडे में मचाया तहलका अंशुल को मैनचेस्टर टेस्ट में धीमी रफ्तार के कारण आलोचना झेलना पड़ा अंशुल गेंदबाजी करते हुए केवल 22 रन खर्च किए और 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए भारतीय क्रिकेट टीम को एक नया स्विंग और स्पीड स्टार मिल गया है। हरियाणा के 25 वर्षीय तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड वनडे में अपनी घातक गेंदबाजी से विपक्षी टीम की कमर तोड़ दी।



मैनचेस्टर टेस्ट में धीमी रफ्तार (125 kmph) के कारण आलोचना झेलने वाले अंशुल ने न सिर्फ अपनी गति को बढ़ाकर 140 kmph किया, बल्कि ऑकलैंड में 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब जीतकर आलोचकों को करारा जवाब दिया है। ऑकलैंड में अंशुल का जादुई स्पेल न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड वनडे में अंशुल कंबोज टीम इंडिया की जीत के सबसे बड़े हीरो साबित हुए। उन्होंने अपने 10 ओवर के कोटे में बेहद कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए केवल 22 रन खर्च किए और 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। इस दौरान उन्होंने 2 ओवर मेडन भी डाले। अंशुल की सबसे बड़ी खूबी यह रही कि उन्होंने कीवी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया और लगातार सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर दबाव बनाए रखा। मैनचेस्टर टेस्ट की नाकामी, फिर... दरअसल, अंशुल कंबोज का अंतरराष्ट्रीय करियर का सफर आसान नहीं रहा है।

जुलाई 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट में उन्हें चोटिल अर्शदीप सिंह (उंगली में चोट) की जगह अचानक टीम में शामिल किया गया था।

टीम मैनेजमेंट को उम्मीद थी कि अंशुल 135 से 140 kmph की रफ्तार से गेंदबाजी करेंगे, लेकिन वहां दबाव में उनकी गति घटकर महज 125 किलोमीटर प्रति घंटे रह गई थी।

इजराइल में प्रधानमंत्री चुनने की कवायद तेज! क्या नेतन्याहू को फिर मिलने जा रही सत्ता? परामर्श का दौर जारी

इजराइल में आम चुनाव के बाद पीएम चुनने की प्रक्रिया तेज है। यहां किसी को बहुमत नहीं मिलने के बाद नई संसद सदस्यों के साथ राष्ट्रपति हर्जोग ने परामर्श की। इजराइल के राष्ट्रपति हर्जोग ने पीएम चयन को लेकर बैठक की विभिन्न दलों के साथ परामर्श का दूसरा दिन शुरू किया। इजरायल में आम चुनाव के नतीजे में स्पष्ट बहुमत नहीं है इजरायल में आम चुनाव के नतीजे आने के प्रधानमत्री चुनने की कवायद शुरू है। चुनाव परिणाम में किसी को स्पष्ट बहुमत न मिलने के बाद, इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने नई चुनी गई नेसेट (संसद) पार्टियों के साथ राजनीतिक परामर्श का दूसरा दिन शुरू कर दिया है। इसका मकसद यह तय करना है कि कौन सा नेता देश की अगली सरकार बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। 'द टाइम्स ऑफ इजराइल' की एक रिपोर्ट के अनुसार, ये औपचारिक बातचीत कल शाम को छोटे संसदीय गुटों- जिनमें रिलिजियस जायोनिज्म, शस, यिसराएल बेतेनु और जेहुत शामिल हैं। उनके साथ शुरू हुई थी। राष्ट्रपति भवन से लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है इन चर्चाओं का यरूशलेम स्थित राष्ट्रपति भवन से सीधा प्रसारण (लाइव ब्रॉडकास्ट) किया जा रहा है। इसके लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। राजनीतिक मुलाकातों के इस सिलसिले के अंत में, गादी आइसेनकोट के 'यशार' गुट ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, और उसके बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की 'लिकुड' पार्टी ने उनसे बातचीत की। औपचारिक अनुरोध किया जा रहा है इस प्रक्रिया के दौरान, हर गुट से औपचारिक रूप से अनुरोध किया जाता है कि वे प्रधानमंत्री पद के लिए किसी



संभावित उम्मीदवार का समर्थन करें। इसके बाद, राष्ट्राध्यक्ष यह तय करते हैं कि किस राजनीतिक नेता को गठबंधन सरकार बनाने का पहला मौका (जनादेश) दिया जाए। इजराइल के कानूनी प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपति को उस सांसद को सरकार बनाने के लिए चुनना होता है जिसके सफल होने की सबसे अधिक संभावना हो; यह जरूरी नहीं है कि सबसे ज्यादा संसदीय सीटें जीतने वाली पार्टी को ही यह मौका मिले। कई दलों ने नेतन्याहू को समर्थन दिया 'द जेरूसलम पोस्ट' के अनुसार, बुधवार की राजनीतिक चर्चाओं के दौरान, 'रिलिजियस जायोनिस्ट पार्टी', 'शास' और 'जेहुत' ने भी नेतन्याहू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन दिया है।

दूसरी ओर, 'याशर', 'डेमोक्रेट्स', 'बीयाचाद' और 'राआम' ने कहा है कि वे 'याशर' के नेता गादी आइसेनकोट का समर्थन करेंगे। 'द टाइम्स ऑफ इजराइल' और 'द जेरूसलम पोस्ट' के अनुसार, एविग्डोर लिबरमैन के नेतृत्व वाली 'इज़राइल बेतेनु' पार्टी ने भी नई सरकार बनाने के लिए आइसेनकोट को ही अपना पसंदीदा उम्मीदवार बताया है। इस बीच, 'यूनाइटेड टोरा जुडाइज्म' के 'देगेल हाटोराह' गुट के चार प्रतिनिधियों ने कहा है कि वे किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे, जबकि 'अगुदात इज़राइल' के तीन सदस्यों ने अभी तक अपना रुख सार्वजनिक नहीं किया है।

26वीं संसद का पहला सत्र आयोजित होगा अरब-बहुल 'जॉइंट लिस्ट' ने भी अभी तक अपना अंतिम फैसला नहीं सुनाया है; वे या तो आइसेनकोट का समर्थन कर सकते हैं या फिर तटस्थ रह सकते हैं।

चुनाव जीतते ही एक्शन में आए डेमोक्रेट, ट्रंप पर लगाम लगाने का प्लान तैयार, ईरान युद्ध को बनाएंगे हथियार!



अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। वरिष्ठ सांसद एडम स्मिथ ने ईरान युद्ध और रक्षा ठेकों को लेकर पेंटागन की कड़ी निगरानी की मांग की है। एडम स्मिथ ने पेंटागन के कामकाज की कड़ी निगरानी की मांग की ईरान युद्ध और निजी कंपनियों के रक्षा ठेकों की जांच होगी एक ट्रिलियन डॉलर से अधिक के रक्षा बजट पर भी सवाल उठाए अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। डेमोक्रेट्स ने अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में बहुमत हासिल कर लिया है। इसी बीच डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ सांसद एडम स्मिथ ने संकेत दिए हैं कि पार्टी जल्द ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पर लगाम लगा सकती है। स्मिथ ने ईरान युद्ध, लैटिन अमेरिका में अमेरिकी सैन्य अभियानों और निजी कंपनियों को दिए जा रहे रक्षा ठेकों को लेकर पेंटागन की कड़ी निगरानी की मांग की है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सशस्त्र सेवा समिति में डेमोक्रेटिक पार्टी के शीर्ष सदस्य स्मिथ ने 120वीं कांग्रेस के लिए अपनी पार्टी की निगरानी संबंधी प्राथमिकताएं सामने रखीं। उन्होंने कहा, अगली कांग्रेस में रक्षा विभाग और ट्रंप प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना मेरी प्राथमिकता होगी। पेंटागन के कामकाज और रक्षा ठेकों की जांच पर जोर स्मिथ ने पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारियों की सार्वजनिक गवाही बढ़ाने और समिति में निगरानी एवं जांच के लिए समर्पित उपसमिति को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव रखा है। ईरान के साथ जारी संघर्ष को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करते हुए उन्होंने इसे 'अवैध युद्ध' करार दिया। हालांकि, यह उनकी राजनीतिक और कानूनी राय है। उन्होंने अपने बयान में इसके समर्थन में कोई विस्तृत कानूनी विश्लेषण पेश नहीं किया।

भारत-गुयाना के बीच डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े समझौते पर सहमति, द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत-गुयाना के बीच द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। सड़क, स्वास्थ्य और रक्षा परियोजनाओं के लिए ऋण सुविधा को बढ़ाने की घोषणा की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर की गुयाना के राष्ट्रपति से मुलाकात डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े समझौते पर सहमति बनी सड़क, स्वास्थ्य और रक्षा प्रोजेक्ट के लिए बड़ी घोषणआ विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। इसमें 'डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर' से जुड़ा समझौता और गुयाना में UPI जैसी प्रणाली को लागू करने पर चर्चा शामिल थी। एक्स पर पर एक पोस्ट में, जयशंकर ने सड़क, स्वास्थ्य और रक्षा परियोजनाओं के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की 'लाइन ऑफ क्रेडिट' (ऋण



सुविधा) बढ़ाने की घोषणा की। दोनों देशों के बीच MoU साइन विदेश मंत्री ने लिखा कि गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. इरफान अली से मिलकर खुशी हुई।

हमने अपने द्विपक्षीय सहयोग में हो रही निरंतर प्रगति की समीक्षा की, खासकर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद। सड़क, स्वास्थ्य और रक्षा परियोजनाओं के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की 'लाइन ऑफ क्रेडिट' बढ़ाने की घोषणा की।

उन्होंने आगे बताया कि दोनों नेताओं ने MSE (सूक्ष्म और लघु उद्यम) विनिर्माण परियोजनाओं की आपूर्ति और स्थापना, तथा 'क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स' (त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाओं) को लागू करने के लिए अनुदान सहायता से जुड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए। नवंबर 2024 में पीएम का गुयाना दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2024 में गुयाना का दौरा किया था।

क्या महाभियोग से छीन जाएगी डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी? मिडटर्म चुनाव हारने के बाद



अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की हार के बाद डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग का खतरा बढ़ा। जानिए क्या डेमोक्रेट्स उन्हें तीसरी बार पद से हटाने की कोशिश करेंगे। मिडटर्म चुनाव में हार के बाद डेमोक्रेट्स को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बहुमत मिला। ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में दो बार महाभियोग का सामना कर चुके हैं। डेमोक्रेट्स महाभियोग चला सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के लिए सीनेट में दो-तिहाई बहुमत जरूरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए मिडटर्म चुनाव के नतीजे बड़ा राजनीतिक झटका लेकर आए हैं। रिपब्लिकन पार्टी ने कांग्रेस के दोनों सदनों में अपना नियंत्रण खो दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बहुमत हासिल कर लिया है।

ईरान ने जर्मन विदेश मंत्री को सुनाई खरी-खरी, अमेरिका-इजरायल के हमले को सही ठहराने पर जताई नाराजगी

ईरान ने जर्मन विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल के बयान की कड़ी निंदा की है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका-इजरायल हमले को जायज ठहराने पर इसे 'शर्मनाक और नैतिक पतन' बताया। ईरान ने जर्मन विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल के बयान पर आपत्ति जताई इस्माइल बाघेई ने चांसलर मर्ज की पुरानी टिप्पणी का हवाला दिया तेहरान ने युद्ध के मानवीय और आर्थिक नुकसान का मुद्दा उठाया ईरान ने जर्मन विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है जिसमें उन्होंने तेहरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले को उचित करार दिया था। गुरुवार को ईरानी विदेश मंत्रालय ने उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे एक शर्मनाक और निम्न स्तर का बयान'



करार दिया। मंत्रालय ने इसके साथ ही जर्मन नेता को इस प्रकार के बयान देने से बचने की सलाह दी। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट के जरिए जर्मन विदेश मंत्री वाडेफुल की आलोचना की। उन्होंने वाडेफुल को जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की पुरानी टिप्पणी याद दिलाई। मर्ज ने ईरान पर हमले की निंदा करते हुए इसे गंदा काम बताया था। ईरानी विदेश मंत्रालय ने मर्ज को घेरा इस्माइल बाघेई एक्स पोस्ट में लिखा, एक समय चांसलर मर्ज ने बड़े उत्साह से कहा था कि इजरायल, ईरान पर हमला करके 'गंदा काम' कर रहा है। लेकिन कुछ ही महीनों बाद, वही चांसलर अब इस बात पर अफसोस जता रहे हैं कि इस युद्ध की वजह से यूरोपीय अर्थव्यवस्था को 100 अरब यूरो का नुकसान हो रहा है। बाघेई ने आगे लिखा, अब उनके विदेश मंत्री भी ईरान पर हुए सैन्य हमले को सही ठहराने के लिए मजबूर महसूस कर रहे हैं। बाघेई ने आगे कहा कि वे इतनी उदासीनता और गहरे नैतिक पतन का शिकार हैं कि न तो उन्हें इंसानी जानों के नुकसान और युद्ध अपराधों का एहसास है, और न ही वे उस आर्थिक नुकसान को समझ पा रहे हैं जो यह युद्ध उनके अपने देश और पूरे यूरोप को पहुंचा रहा है। जर्मन कहावत के साथ खत्म की बात बाघेई ने एक जर्मन कहावत के जरिए अपनी बात खत्म की।

शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में

वैध बताया। शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे गुट की मांग पर सवाल उठाए। बुधवार को शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील ध्रुव मेहता ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ के सामने दलील दी कि जिन विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की जा रही है, उस महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है। ऐसे में विधायकों की अयोग्यता की मांग का अब कोई व्यावहारिक महत्व नहीं रह गया है। यह विवाद वर्ष 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे की बगावत से जुड़ा है। उस समय शिवसेना के कई विधायकों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे को अपना नेता चुना था। इसके बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने की दलील उद्धव ठाकरे गुट ने शिंदे के नेतृत्व में हुई बगावत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ठाकरे गुट ने बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग के साथ ही चुनाव आयोग और विधानसभा अध्यक्ष के उन फैसलों को भी चुनौती दी है, जिनके तहत शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को दिया गया था। ध्रुव मेहता ने दलील दी कि अब विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, इसलिए विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग पर विचार करने का औचित्य नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में शिंदे के नेतृत्व में बनी सरकार को शिवसेना के अधिकांश विधायकों का समर्थन प्राप्त था। विधानसभा अध्यक्ष के अधिकारों का किया उल्लेख मेहता ने दलबदल विरोधी कानून का हवाला देते हुए कहा कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास है। उन्होंने 'किहोटो होलोहन' मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष इस प्रक्रिया में एक न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) की तरह काम करते हैं। ऐसे में उनके फैसलों की न्यायिक समीक्षा सीमित दायरे में ही की जा सकती है। शिंदे गुट के नेता और मुख्य प्रतोद की नियुक्ति को बताया वैध शिंदे गुट के वकील ने 21 जून 2022 को हुई विधायकों की बैठक का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इस बैठक में एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुना गया था और भरत गोगावले को मुख्य प्रतोद नियुक्त किया गया था। मेहता के मुताबिक, ये दोनों फैसले वैध थे। उन्होंने राजेंद्र सिंह राणा और सुभाष देसाई मामलों का उल्लेख करते हुए दोहराया कि ठाकरे गुट की ओर से विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग अब अप्रासंगिक हो चुकी है। ये सभी दलीलें शिंदे गुट के वकील की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रखी गईं।

हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को

संबंधित प्रवर्गों के विद्यार्थियों को आर्थिक राहत मिलेगी। महाराष्ट्र पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के इंटर्नशिप भत्ते में वृद्धि की गई है। हैदराबाद (सिंध) नेशनल कॉलेजिएट यूनिवर्सिटी, मुंबई के समूह विश्वविद्यालय में कुलाधिकारी पद के कार्यकाल और आयु सीमा की शर्त हटाने तथा कुलगुरु पद पर कार्यरत व्यक्ति को पुनर्नियुक्ति के योग्य बनाने के लिए अधिसूचना में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। एक संपादकीय सावधानी: मूल सामग्री में पशु चिकित्सा विद्यार्थियों के बढ़े हुए इंटर्नशिप भत्ते की नई राशि नहीं दी गई है। किसानों के 73 लाख खातों में 5,000 दिवाली से पहले महाराष्ट्र के किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए राज्य सरकार ने सूखा सहायता और कर्जमाफी की राशि सीधे बैंक खातों में जमा की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि सूखाग्रस्त किसानों के लिए घोषित 5 हजार रुपये की अग्रिम सहायता अब तक 73 लाख किसानों के खातों में पहुंच चुकी है। अगले दो दिनों में करीब 95 प्रतिशत लाभार्थियों तक यह राशि पहुंचने की उम्मीद है। नागपुर में कृषि सुविधा केंद्र नागपुर जिले की बिडगांव-तरोड़ी (खुर्द)-पांढुर्णा नगर पंचायत को प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए 1 हेक्टेयर 86 आर जमीन दी जाएगी। डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के नागपुर स्थित कृषि महाविद्यालय की दाभा परिसर की जमीन पर अंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 644 करोड़ 63 लाख रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा नादेड़ जिले के मुखेड में वरिष्ठ स्तर का नियमित दीवानी न्यायालय स्थापित किया जाएगा।

समृद्धि महामार्ग पर बड़ा हादसा! गश्त कर रही पुलिस वैन को दोहरी टक्कर, 3 पुलिसकर्मी घायल



समृद्धि महामार्ग पर चैनल क्रमांक 162 के पास गश्त कर रही पुलिस वैन को दो वाहनों ने टक्कर मार दी। हादसे में तीन पुलिसकर्मी घायल, कारंजा अस्पताल में भर्ती। 3 नवंबर की रात समृद्धि महामार्ग पर हुआ हादसा। चैनल क्रमांक 162 के पास यू-टर्न लेते समय पुलिस वैन को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। टक्कर के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पीछे से आए एक अन्य वाहन ने भी पुलिस वैन को टक्कर मारी। तीनों घायल पुलिसकर्मियों को कारंजा उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग पर 3 नवंबर की रात चैनल क्रमांक 162 के पास गश्त कर रही पुलिस वैन को दो वाहनों ने टक्कर मार दी। हादसे में तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कारंजा उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गश्त के दौरान हुआ हादसा अकोला कारंजा लाड, नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग पर गश्त कर रही पुलिस वैन को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में वैन में सवार तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना मंगलवार, 3 नवंबर की रात चैनल क्रमांक 162 के पास हुई। हादसे के बाद टक्कर मारने वाला वाहन चालक मौके से फरार हो गया। इस घटना ने एक बार फिर महामार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। यू-टर्न लेते समय मारी टक्कर प्राप्त जानकारी के अनुसार, जगदीश घरडे (48), अलीम शेख (29) और तोहीम शेख (27) पुलिस वैन क्रमांक एमएच-12, जेडसी-5346 से समृद्धि महामार्ग के नागपुर कॉरिडोर में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान चैनल क्रमांक 162 के पास पुलिस वैन यू-टर्न ले रही थी। तभी एक अज्ञात वाहन ने वैन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद संबंधित वाहन चालक बिना रुके मौके से फरार हो गया। इसी बीच पीछे से आ रहे एक अन्य वाहन ने भी पुलिस वैन को टक्कर मार दी। इस दोहरी टक्कर के कारण वैन में सवार तीनों पुलिसकर्मी घायल हो गए। 108 एंबुलेंस ने पहुंचाया अस्पताल हादसे की सूचना मिलते ही समृद्धि महामार्ग की 108 एंबुलेंस सेवा का दल तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा। आईसी-08 स्थित एंबुलेंस के पायलट रवि (सोनू) शिंदे और डॉ. गणेश ने तीनों घायलों को प्राथमिक उपचार दिया। इसके बाद उन्हें आगे के उपचार के लिए कारंजा उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। महामार्ग पर पुलिस की गश्त के दौरान हुई इस दुर्घटना से सुरक्षा व्यवस्था और तेज रफ्तार वाहनों की निगरानी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

शेयर बाजार में दिवाली की रौनक, 2,008 अंक उछला सेंसेक्स; निवेशकों की कमाई में बंपर उछाल



भारतीय शेयर बाजार में दिवाली की रौनक देखने को मिल रही है। जहां सेंसेक्स 2,008 अंकों की उछाल दर्ज की गई। निवेशकों की कमाई में 28 लाख करोड़ रुपये का बंपर इजाफा हुआ। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को लगातार छठे कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ बंद हुआ। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 2,008.61 अंक की तेजी के साथ 79,310.0 पर था। तेजी के कारण बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केटकैप 28 लाख करोड़ रुपये बढ़ा। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को लगातार छठे कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ बंद हुआ। दिन के अंत में सेंसेक्स 2,008.61 अंक या 2.60 प्रतिशत की तेजी के साथ 79,310.01 और निफ्टी 576 अंक या 2.40 प्रतिशत की मजबूती के साथ 24,536.60 पर था। बाजार में लगातार छह दिनों की तेजी के कारण बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड सभी कंपनियों का मार्केटकैप करीब 28 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 501 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है, जो कि 28 अक्टूबर को 473 लाख करोड़ रुपये था। कारोबारी सत्र में बाजार में व्यापक तेजी कारोबारी सत्र में बाजार में व्यापक आधार पर तेजी देखी गई। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 106.05 अंक या 0.56 प्रतिशत की तेजी के साथ 19,132.45 और निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 1,115.40 अंक या 1.87 प्रतिशत की बढ़त के साथ 60,620.90 पर था। सूचकांकों में निफ्टी ऑटो (4.14 प्रतिशत), निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज (3.99 प्रतिशत) और निफ्टी रियल्टी (3.52 प्रतिशत) टॉप गेनर्स थे। इसके अलावा, निफ्टी प्राइवेट बैंक (3.44 प्रतिशत), निफ्टी पीएसयू बैंक (3.13 प्रतिशत), निफ्टी आईटी (2.42 प्रतिशत), निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स (2.32 प्रतिशत), निफ्टी सर्विसेज (2.16 प्रतिशत), निफ्टी कंज्पशन (1.94 प्रतिशत) और निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग (1.29 प्रतिशत) सबसे ज्यादा बढ़ने वाले सूचकांक थे। दूसरी तरफ निफ्टी इंडिया डिफेंस (1.69 प्रतिशत), निफ्टी मीडिया (0.84 प्रतिशत), निफ्टी एनर्जी (0.52 प्रतिशत) और निफ्टी पीएसई (0.02 प्रतिशत) की गिरावट के साथ बंद हुए। आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स सूचकांकों में बजाज फाइनेंस, इंटरग्लोब एविएशन, आईसीआईसीआई बैंक, मारुति सुजुकी, एमएंडएम, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, इटरनल, अल्ट्राटेक सीमेंट, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, सन फार्मा, एलएंडटी, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, कोटक महिंद्रा बैंक, टाइटन, टाटा स्टील, एचयूएल और ट्रेंट गेनर्स थे। भारती एयरटेल, पावर ग्रिड, आईटीसी, बीईएल और एनटीपीसी लूजर्स थे।

पृष्ठ 1/8 का शेष

दिवाली-छठ पर मुंबई के रेलवे

उपकरणों और वॉर रूम से निगरानी रखी जा रही है। दिवाली और छठ पूजा के दौरान मुंबई के प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मध्य रेल अलर्ट हो गया है। बाहर गांव जाने वाली ज्यादातर स्पेशल ट्रेनें एलटीटी से छोड़ी जा रहीं हैं। यहां व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रियों की सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए मध्य रेल के महाप्रबंधक राजीव श्रीवास्तव ने एलटीटी का निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं और भीड़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। 98 विशेष ट्रेनें निरीक्षण के दौरान जीएम ने यात्री प्रतीक्षा क्षेत्रों, टिकट काउंटरों, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की आवाजाही सुचारू बनाए रखने के लिए सतर्कता बरतें और आपसी समन्वय के साथ लगातार निगरानी करें। मध्य रेल त्योहारी सीजन में नियमित ट्रेनों के अतिरिक्त एलटीटी से विभिन्न गंतव्यों के लिए 98 विशेष ट्रेनें चला रहा है। एलटीटी से प्रतिदिन दोनों दिशाओं में कुल 54 नियमित ट्रेन सेवाओं के साथ 10 विशेष ट्रेन सेवाओं का भी संचालन किया जा रहा है। प्रतीक्षा क्षेत्र से लेकर सुरक्षा तक विशेष इंतजाम यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर ढके हुए शेड के साथ विशेष प्रतीक्षा क्षेत्र बनाए गए हैं, ताकि यात्रियों को व्यवस्थित तरीके से प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया जा सके। यात्रियों के मार्गदर्शन और सहायता के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF), टिकट जांच कर्मचारियों और वाणिज्यिक कर्मचारियों की तैनाती की गई है। स्टेशन पर पर्याप्त रोशनी, वेंटिलेशन, पंखे, पेयजल, शौचालय, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, खाद्य स्टॉल और सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली की व्यवस्था की गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए पर्याप्त टिकट काउंटर भी उपलब्ध कराए गए हैं। एआई से होगी भीड़ की निगरानी भीड़ प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) उपकरणों और समर्पित वॉर रूम के माध्यम से टिकट उपलब्धता तथा यात्रियों की आवाजाही के रुझान पर वास्तविक समय में नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के लिए आरपीएफ और राजकीय रेलवे पुलिस (GRPF) के साथ समन्वय बनाए रखा गया है। महाप्रबंधक ने अधिकारियों को सतर्क रहने और लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए। मध्य रेल ने भरोसा दिलाया है कि त्योहारों के दौरान यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और सुगम रेल यात्रा उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। भीड़ और भ्रम की स्थिति से बचने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर पहले से निर्धारित किए जा रहे हैं तथा उनमें बदलाव से बचने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षित चढ़ने-उतरने की व्यवस्था बनाए रखने के लिए आइलैंड प्लेटफॉर्म पर दो भीड़भाड़ वाली ट्रेनों को एक साथ नहीं रखा जा रहा है। ट्रेनों के समय और प्लेटफॉर्म की जानकारी नियमित रूप से उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से दी जा रही है। आरपीएफ और वाणिज्यिक कर्मचारियों की निगरानी में यात्रियों के लिए कतार व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का असर

में आ गया। बोरीवली पूर्व में BEST बस डिपो के लिए आरक्षित जमीन से अतिक्रमण हटाने में विफल रहने पर अदालत की फटकार के बाद बुधवार सुबह बीएमसी ने बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान 27 व्यावसायिक ढांचों को ध्वस्त कर करीब 3,400 वर्ग मीटर जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई। बीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट को भी जानकारी दी कि विवादित भूखंड से सभी अतिक्रमित निर्माण हटा दिए गए हैं। 3,400 वर्ग मीटर जमीन से हटाए 27 व्यावसायिक ढांचे मुंबई बीएमसी के आर मध्य विभाग ने बोरीवली पूर्व के स्वामी विवेकानंद मार्ग स्थित भूखंड पर यह कार्रवाई की। नगर सर्वेक्षण क्रमांक 15 और नगर नियोजन योजना-2 के अंतर्गत आने वाली भूखंड संख्या 7बी की जमीन BEST बस डिपो के लिए आरक्षित है। यहां लंबे समय से व्यावसायिक अतिक्रमण था। पुलिस बंदोबस्त के बीच प्रशासन ने विशेष अभियान चलाकर सभी 27 ढांचे हटा दिए। 70 मजदूर और दो जेसीबी मशीनें रहीं तैनात अतिक्रमण हटाने के अभियान में बीएमसी के इंजीनियरों और कर्मचारियों के साथ करीब 70 मजदूर शामिल थे। कार्रवाई के लिए दो जेसीबी मशीनों और चार डंपरों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस बल की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया पूरी की गई। अब इस जमीन का इस्तेमाल BEST बस डिपो के मूल उद्देश्य के लिए करने का रास्ता साफ हुआ है। सु स्थायी समिति में अधिकारियों के निलंबन की मांग बुधवार शाम मुंबई बीएमसी की स्थायी समिति की बैठक में विधि विभाग के संबंधित अधिकारियों को निलंबित करने की मांग उठी। समिति का आरोप था कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण अदालत में बीएमसी का पक्ष प्रभावी तरीके से नहीं रखा गया।

गोकुल डेयरी विवाद: राहुल

देखने को मिल रही है, जिसे लेकर विपक्ष अब सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस नेता सतेज पाटिल ने इस पूरे घटनाक्रम को कोल्हापुर की जनता के स्वाभिमान पर सीधा हमला बताया है और इसके विरोध में 9 नवंबर को दशहरा चौक से जिला कलेक्टर कार्यालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकालने का एलान किया है। इसके साथ ही एनसीपी (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार ने लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सभी लोगों से अपील की है कि वे चेयरमैन पद के चुनाव के दौरान गोकुल डेयरी का घेराव करें, जिससे इस फैसले का पुरजोर विरोध किया जा सके। गोकुल डेयरी का अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा महत्व? कोल्हापुर स्थित यह सहकारी डेयरी केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि पश्चिमी महाराष्ट्र के लाखों किसानों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो सीधे तौर पर उनकी आजीविका से जुड़ा हुआ है। यह डेयरी लगभग 5.5 लाख किसानों से रोज करीब 20 लाख लीटर दूध का संग्रहण करती है और बदले में उन्हें हर 10 दिन के अंतराल पर लगभग 100 करोड़ रुपये का भुगतान करती है। यही वजह है कि इस संस्था के प्रबंधन और चुनाव परिणामों में फेरबदल की कोशिशों को लेकर स्थानीय दूध उत्पादकों और राजनीतिक दलों के बीच तीखा आक्रोश बना हुआ है।

खाडीपार में अवैध हुक्का पार्लर पर पुलिस का छापा, पांच लोगों पर मामला दर्ज

बिना अनुमति ग्राहकों को पिला रहे थे तंबाकू मिश्रित हुक्का; दो पॉट, पाइप और चिलम जब्त

सिटी न्यूज़ मुंबई/गनी खान

भिवंडी के खाडीपार इलाके में अवैध रूप से संचालित हुक्का पार्लर पर निजामपुरा पुलिस ने छापा मारकर पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मौके से हुक्का पीने में इस्तेमाल होने वाला सामान भी जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक, 4 नवंबर की रात करीब 11:10 बजे खाडीपार में समीर सर्विस सेंटर के पीछे ब्रिज के पास बिना अनुमति हुक्का पार्लर चलाए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद निजामपुरा पुलिस ने मौके पर छापा मारा। पुलिस का आरोप है कि सज्जाद अख्तर अंसारी (22), राजकुमार मुकेश कुमार यादव (36), रईस अहमद अजगर अली अंसारी (47), गणेश गोरांगु देवनाच (42) और संजय जगदीश कुमार (35) मिलकर ग्राहकों को तंबाकू मिश्रित फ्लेवर वाला हुक्का उपलब्ध करा रहे थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 1,400 रुपये कीमत के दो कांच के हुक्का पॉट, तीन रबर पाइप और मिट्टी की चिलम जब्त की। सभी पांचों आरोपियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) के तहत नोटिस देकर छोड़ दिया गया। निजामपुरा पुलिस स्टेशन में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच पुलिस हवलदार कांबले कर रहे हैं। उधारी के पैसे मांगने पर दो दोस्तों पर हमला, एक गंभीर रूप से घायल विवाद के बाद लकड़ी के डंडे और लोहे की रॉड से किया हमला; आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज सिटी न्यूज़ मुंबई/गनी खान भिवंडी के मुर्तजा कंपाउंड इलाके में उधारी के पैसे मांगना दो दोस्तों को भारी पड़ गया। पैसों के विवाद में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर दो दोस्तों के साथ मारपीट की। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, घटना 4 नवंबर की रात करीब 12:30 से 12:45 बजे के बीच चोबी तलाव इलाके में जामा मस्जिद, फारूकनिया के पास हुई। समदनगर निवासी रिजवान शाहीदनूर सय्यद (35) ने अजमेरनगर निवासी ऐजाज अली अशीमुल्लाह चौधरी (35) के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक, रिजवान ने जब ऐजाज से उधारी के पैसे मांगे तो दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि ऐजाज ने गाली-गलौज करते हुए रिजवान के साथ मारपीट की और उन्हें जबरन गाड़ी में बैठाकर ले जाने की कोशिश की। इस दौरान रिजवान के दोस्त शिवम ने बीच-बचाव किया तो आरोपी ने पहले लकड़ी के डंडे और फिर गाड़ी में रखी लोहे की रॉड से उस पर हमला कर दिया। हमले में शिवम गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप है कि हमलावर ने दोनों दोस्तों को जान से मारने की धमकी भी दी। भोईवाड़ा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

भिवंडी में 80 हजार रुपये का कीमत का 17 ग्राम मेफेड्रोन बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

तीसरे की तलाश जारी,भारत कंपाउंड में शांतिनगर पुलिस की कार्रवाई

सिटी न्यूज़ मुंबई/गनी खान

भिवंडी में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शांतिनगर पुलिस ने भारत कंपाउंड इलाके में छापेमारी कर 80 हजार 200 रुपये कीमत का 17 ग्राम मेफेड्रोन (MD) ड्रग्स जब्त किया है। पुलिस ने मौके से दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले में शामिल गोलू नामक तीसरे संदिग्ध की तलाश की जा रही है। पुलिस के अनुसार, 4 नवंबर को सुबह करीब 8:13 बजे भारत कंपाउंड स्थित सबका होटल के पास पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान फैजान जमील अहमद अंसारी (24), निवासी सुभाषनगर और अनवर युसुफ शेख (30), निवासी गुलजारनगर, भिवंडी के कब्जे से 17 ग्राम मेफेड्रोन बरामद किया गया।पुलिस ने जब्त किए गए मादक पदार्थ की कीमत 80 हजार 200 रुपये आंकी है। जांच में गोलू नामक एक अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आने के बाद उसे भी मामले में आरोपी बनाया गया है।इस मामले में शांतिनगर पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8(सी) और 21(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और फरार संदिग्ध की तलाश जारी है। मामले की जांच पुलिस निरीक्षक पवार कर रहे हैं।

28 मार्च 2027 से नवी मुंबई एयरपोर्ट पर होंगी 14 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शिफ्ट, मुंबई T1 का पुनर्विकास शुरू



मुंबई एयरपोर्ट के T-1 पुनर्विकास के दौरान 14 अंतरराष्ट्रीय शहरों की उड़ानें नवी मुंबई शिफ्ट करने का प्रस्ताव। 28 मार्च 2027 से लागू करने का सुझाव। मुंबई एयरपोर्ट से 14 अंतरराष्ट्रीय शहरों की उड़ानें नवी मुंबई शिफ्ट हो सकती हैं। 28 मार्च 2027 से बदलाव का प्रस्ताव, इंडिगो, एयर इंडिया और अकासा भी सहमत। टर्मिनल-1 की क्षमता 1.5 से बढ़ाकर 2 करोड़ यात्री सालाना होगी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 के पुनर्विकास से पहले 14 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों की उड़ानें नवी मुंबई एयरपोर्ट पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। नई व्यवस्था 28 मार्च 2027 से लागू करने की योजना है। इससे टर्मिनल-1 की यात्री क्षमता बढ़ाने का रास्ता तैयार होगा। नवी मुंबई से संचालित हो सकती हैं 14 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 के पुनर्विकास की तैयारी के बीच 14 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों की उड़ानें नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थानांतरित की जा सकती हैं। विदेशी विमानन कंपनियों ने इस संबंध में प्रस्ताव दिया है। वहीं, इंडिगो, एयर इंडिया और अकासा एयर ने भी अपनी कुछ उड़ानों को नवी मुंबई एयरपोर्ट पर स्थानांतरित करने पर सहमति जताई है। प्रस्तावित योजना के अनुसार, यह नई व्यवस्था 28 मार्च 2027 से लागू की जा सकती है। इसके तहत बहरीन, दमाम, ढाका, दोहा, जकार्ता, जेद्दा, काठमांडू, कुवैत, मदीना, मस्कट, रियाद और शारजाह सहित 14 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों की उड़ानें नवी मुंबई से संचालित हो सकती हैं। टर्मिनल-1 के पुनर्विकास की तैयारी मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 का पुनर्विकास अप्रैल 2027 से शुरू करने की योजना है। इस परियोजना के तहत टर्मिनल की यात्री क्षमता मौजूदा 1.5 करोड़ से बढ़ाकर सालाना 2 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, मुंबई एयरपोर्ट की कुल वार्षिक यात्री क्षमता को 5.5 करोड़ से बढ़ाकर 6.5 करोड़ तक ले जाने की योजना है। पुनर्विकास के दौरान उड़ानों के संचालन में होने वाली संभावित दिक्कतों को कम करने के लिए कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को नवी मुंबई स्थानांतरित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यात्री सुविधाओं पर होगा असर प्रस्तावित बदलाव के तहत एक ही शहर के दो अलग-अलग हवाई अड्डों से उड़ानों का संचालन होगा। इससे यात्रियों को टिकट बुक करते समय और यात्रा से पहले अपने प्रस्थान हवाई अड्डे की जानकारी ध्यान से जांचनी होगी। योजना के अनुसार, उड़ानों के स्थानांतरण के बावजूद मुंबई एयरपोर्ट क मौजूदा यातायात क्षमता का करीब 91 प्रतिशत हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। हालांकि, अंतिम संचालन व्यवस्था और स्थानांतरित होने वाली उड़ानों की सूची पर संबंधित विमानन कंपनियों और एयरपोर्ट प्रबंधन के फैसले के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।

शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 4.42 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप, बोरीवली में 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

मुंबई, (सिटी न्यूज़ मुंबई)

शेयर बाजार में निवेश कर अधिक मुनाफा दिलाने का झांसा देकर 4 करोड़ 42 लाख 20 हजार रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले में मुंबई के कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन में छह लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर उनसे संपर्क किया और आकर्षक रिटर्न का भरोसा दिलाया। आरोपियों ने खुद को शेयर बाजार से जुड़ी कंपनियों और निवेश गतिविधियों से संबंधित बताते हुए निवेश के लिए प्रेरित किया। शिकायत



में आरोप लगाया गया है कि जनवरी 2026 में निवेश की प्रक्रिया शुरू हुई। आरोपियों ने अलग-अलग कंपनियों और शेयरों में निवेश के नाम पर रकम जमा करवाई। शिकायतकर्ता के अनुसार, निवेश के दौरान करीब 4 करोड़ 85 लाख 33 हजार 711 रुपये ट्रांसफर किए गए, जबकि बाद में शेयरों की खरीद-बिक्री और रकम के हिसाब में गड़बड़ी सामने आई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि लगभग 1 करोड़ 32 लाख रुपये के शेयरों के लेनदेन में भी अनियमितता हुई और कुल 4 करोड़ 42 लाख 20 हजार रुपये की आर्थिक धोखाधड़ी की गई। इस मामले में उशिक गाला, ध्वनी दत्तानी, राज मेहता, शिखा, महेश गाला और मीना गाला के नाम FIR में दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने 23 अक्टूबर 2026 को FIR क्रमांक 0719 दर्ज की है। मामले में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316(2), 318(4) और 3(5) लगाई गई हैं। पुलिस उपनिरीक्षक रोशन दिलीप देवरे को मामले की जांच सौंपी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। FIR में दर्ज आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

दिवाली-छठ पर मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर उमड़ेगी भीड़, LTT पहुंचे मध्य रेलवे GM ने दिए अलर्ट रहने के निर्देश



दिवाली- छठ पर घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ देखते हुए LTT पर होल्डिंग एरिया, अतिरिक्त स्टाफ और AI निगरानी की व्यवस्था की गई है। GM ने ट्रेनों और सुविधाओं निरीक्षण किया। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक राजीव श्रीवास्तव ने लोकमान्य तिलक टर्मिनस का किया औचक निरीक्षण। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए कुल 98 विशेष ट्रेनों का संचालन हो रहा है। स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आधुनिक एआई ...शेष 7 पर

PUBLIC NOTICE

Anwarul Ahmed Iqbal Ahmed Shaikh , Euphoria 14th Floor, Flat 1406, S. No. 21/2, Apt. 21/2B, Ghodbander, Mira Road East, Mira-Bhayander, P.O. Mira Road, Dist. Thane, Maharashtra – 401107, have changed my name from "Anwarul Iqbal Shaikh" to "Shabina Anwarul Shaikh". Henceforth, I shall be known and identified as "Anwarul Iqbal Shaikh" for Passport .all purposes and in all records, documents and transactions.
Date: 05/11/2026
Place: Mira-Bhayander, Maharashtra
Sd/-
Anwarul Iqbal Shaikh

यह दैनिक मालक-मुद्रक-प्रकाशक, संपादक मोहम्मद शकील अब्दुल रफीक ने सिटी इन्टरप्राजेस धरती कॉम्पलेक्स शॉप नं. 11, एवरशाईन नगर, मिरा रोड (पूर्व), जिल्हा - ठाणे से प्रकाशित किया, मुख्य कार्या लय- धरती कॉम्पलेक्स शॉप नं. 11, एवरशाईन नगर, मिरा रोड (पूर्व), जिल्हा - ठाणे महाराष्ट्र।मुंबई कार्या लय- शॉप नं. 14 उपाध्याय इंडस्ट्रियल इस्टेट, दहिसर चेक नाका, मुंबई इस समाचार पत्र में प्रकाशित सभी समाचारों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है किसी भी विवाद का निपटारा मा. ठाणे न्यायालय के अधीन होगा संपादक मो. शकील अ. रफीक : मो. 9869128483
Email : shakeelsahara@gmail.com / citynewsmumbai@gmail.com website : www.citynewsmumbai.in RNI No. : MAHHIN/2012/47486